

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 27/24

GCMS NO 2024/48

हंसा उर्फ हंसराज पुत्र अर्जुन निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
अपीलांट

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र हरकचंद जैन निवासी 3-घ-17 विज्ञान नगर कोटा
कपूर चंद पुत्र हरकचंद जैन निवासी 1/289 आवासन मण्डल सवाई माधोपुर
2. गौतम जैन पुत्र हरकचंद जैन निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. रामप्यारी पुत्री हरकचंद जैन निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4. उप पंजीयक सवाई माधोपुर
5. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

(अपील विरुद्ध मु0नं0 134/87 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.2.88 न्यायालय उप जिला कलक्टर,
सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री शमाम मोहन शर्मा


अभिभाषक रैस्पो0 श्री कमलेश कुमार जैन

दिनांक 17.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक
16.2.88 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रैस्पो0 संख्या
1 ता 4 के पिता हरकचंद पुत्र गुलाब चंद जैन ने दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं इस्तकरारहक
विरुद्ध अपीलांट व अपीलांट के पिता एवं भाई मोती के विरुद्ध इस आशय का पेश किया कि
ख0न0 1108/2 रकबा 5 विस्वा भूमि दिनांक 27.7.74 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा
आवंटन की गई थी उक्त आराजीयात पर वादी के कब्जे काश्त की आराजीयात रही है। उक्त
आराजीयात को वादी सदैव बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करता चला आ
रहा है। जो जमाबंदी खसरा गिरदावरी सम्वत 2041-44 मे दर्ज है। वादी ने उक्त आराजीयात को
साजे बांटे पर प्रतिवादी को बताई थी किन्तु अब वादी प्रतिवादीगण को साझे बांटे पर काश्त नहीं
बताना चाहते है। प्रतिवादीगण ने एक नाराजय गिरोह बना रखा है जो वादी के उक्त रकबे का
जबरदस्ती लठठ के जोर से छीनना चाहते है। इसी प्रकार से प्रतिवादीगण वादी के साथ झगडा
करने के लिए प्रयत्नशील है तथा आराजी ख0न0 1108/2 रकबा 5 बीघा का उपयोग व उपभोग
मे अवरोध उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील है। दिनांक 12.7.86 को वादी उक्त आराजीयात पर
सायंकाल काश्त कर रहा था तो प्रतिवादीगण हाथो मे लठठ लेकर वादी के खेत पर आ गये व
काश्त करने मे अवरोध पैदा करने लगे व उक्त खेत को जोतने नहीं दिया। तथा कहने लगे कि
आराजी को लठठ के जोर पर प्रतिवादीगण काश्त करेगे। वादी को काश्त नहीं करने देते। इस


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



कार प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकारी नहीं है। अतः वादी को अधिकार हासिल है कि वादी की स्वामित्व की आराजीयात की रक्षा के लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करे तथा वादी के उपयोग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करे। अतः घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि आराजी न तो अतिक्रमण करे तथा काश्त करने में बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी से करावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 हंसा द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको बहस अपील एवं धारा 5 मियाद अधिनियम पर एक साथ सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.2.88 जल्दबाजी में कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है। उक्त निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों से परे होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई है। केवल मात्र वाद पत्र में अंकित तथ्यों को आधार मानकर दस्तावेजी साक्ष्यों पर कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो निरस्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जल्दबाजी में पारित की गई है जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पत्रावली तहत न्यायालय में दिनांक 16.1.88 तक साक्ष्य दावा एवं कायमी तनकीयात 16.2.88 नियत की गई। अदालत मातहत द्वारा उसी दिन तनकी वाद पत्र एवं जबाब दावे के आधार पर कायम करनी चाहिए थी। तथा वाद तनकी उभयपक्षों एवं उनके गवाहों की साक्ष्य लेकर प्रकरण को निर्णित करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने संक्षिप्ततय जल्दबाजी में उपरोक्त निर्णय व डिक्री जारी कर अपीलांट को पाबन्द कर दिया। तथा आधार माना कि आर्डर 8 रूल 5 सीपीसी के तहत आराजी ख०न० 1108/2 को लेकर कोई डिनायल पेश नहीं किया जबकि जबाब दावे में अंकित तथ्य वाद पत्र के मद न० 5 ता 10 को स्वीकार किया है तथा रिलीफ में अपना कब्जा बताते हुए वाद पत्र खारिज करने की इस्तदुआ चाही है। माननीय सुप्रीम न्यायालय की कई नजीरो में स्पष्ट मत पारित किया है कि वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर यदि जबाब दावे में अंकित तथ्य अस्वीकार किये जाते हैं तो तनकीयात कायम कर प्रकरण आयी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य की तुलना कर प्रत्येक इश्यू पर पृथक पृथक मत पारित करना चाहिए। जो उन्होंने नहीं किया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय कानून के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय आर्डर 20 रूल 5 के विपरीत होने से भी निरस्त योग्य है। साबिक ख०न० 1108/2 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम श्यामपुरा में स्थित है जिस पर अपीलांट सदैव से काबिज काश्त रहकर लाभान्वित होता चला आ रहा है व अपना परिवार का


राजस्थ अपील प्राधिकारी
स्थाई न्यायालय

न पोषण करता चला आ रहा है। सरकारी लगान भी अपीलांट जमा कराता है। खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2043 से अपीलांट की खरीफ की फसल काशत होना बखूबी साबित है। वादी/रेस्पों के पिता हरकचंद गलत तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश किया है। उक्त आराजी पर अपीलांट शुरू से काबिज काशत है। रेस्पों का उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होने से धारा 88 व 188 आर टी एक्ट के तहत वाद पत्र पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया ही वाद वादी खारिज होने योग्य था तथा रेस्पों के पिता को बेदखली का दावा लाना चाहिए था जो वह नहीं लाये है। इस बात पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरुद्ध पारित की है। वर्तमान में अपीलांट की फसल सरसब्ज खंडी है तथा आराजीयात को चारों तरफ से डोल मेड होकर तारफेंसिंग, विधुत कनेक्शन बोर बेल अपीलांट द्वारा कराई गई है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 1 अर्जुन पुत्र पन्ना मीना की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके अब एक मात्र पुत्र हंसा अपीलांट है तथा प्रतिवादी संख्या 3 मोती पुत्र अर्जुन लाऔलाद फोट हो चुका है। वाद में वर्णित आराजीयात पर अपीलांट काफी लम्बे समय से लाभान्वित होता चला आ रहा है। रेस्पों का उक्त आराजीयात से कोई संबंध वास्ता नहीं है। अपीलाधीन निर्णय की अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी ना ही अधिनस्थ न्यायालय में उनके अधिवक्ता ने पैरवी की तथा अपीलांट से यह कह रखा था कि जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी सूचना दे दूंगा। लेकिन अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार की कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी। वैसे भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रारंभ से ही शून्य डिक्री की श्रेणी में आने से मियाद प्रभावी नहीं होती है इस प्रकार के आदेश को किसी भी समय सक्षम न्यायालय में चुनौति देकर रद्द कराया जा सकता है। जब अपने अधिवक्ता से आकर अपीलांट मिला तो उन्होंने कहा कि दिनांक 16.2.88 की आपको अपील करनी चाहिए इस पर दिनांक 18.3.24 को नकल प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 21.3.24 को नकल निर्णय व डिक्री प्राप्त की जानकारी से अपील अपीलांट पेश की है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दफा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.2.88 मु०न० 134/87 निरस्त फरमाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज फरमाया जावे।

रेस्पों के अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क दिया कि आराजी ख०न० 1108/2 रकबा 5 विस्वा भूमि दिनांक 27.7.74 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन की गई थी उक्त आराजीयात पर रेस्पों/वादी के कब्जे काशत की आराजीयात रही है। उक्त आराजीयात को वादी सदैव बहैसियत खातेदार काशतकार काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। जो जमाबंदी खसरा गिरदावरी सम्वत 2041-44 में दर्ज है। रेस्पों/वादी ने उक्त आराजीयात को साजे बांटे पर अपीलांट/प्रतिवादी को बताई थी किन्तु अपीलांट उक्त साजे बांटे की आड में उक्त रेस्पों की खातेदारी की आराजीयात को काशत नहीं करने देने एवं रेस्पों को जबरन बेदखल करने पर आमदा होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया था। अपीलांट का कथन रहा कि वादी/रेस्पों को बेदखली का वाद पेश करना चाहिए जबकि बेदखली के वाद विवादित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने पर किया जाता है जबकि विवादित

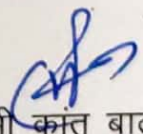
राजस्थान अपील प्राधिकारी
जयपुर

आराजीयात पर रेस्पो/वादी का कब्जा है जो कि जमाबंदी खसरा गिरदावरी सम्वत 2041-44 से पुष्ट है। विवादित आराजीयात को रेस्पो/वादी द्वारा अपीलांट को साजे बांटे पर दी गई थी। जिससे उस समय भूमि पर उनका कब्जा रहा है। परन्तु रेस्पो/वादी द्वारा साजे बांटे पर नही देये जाने के कारण ही वे लोग रेस्पो/वादी को उक्त आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा होने एवं लठठ के जोर से भूमि से बेदखल करने की कोशिश करने के कारण ही वादी/रेस्पो0 द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात पर रेस्पो/वादी का कब्जा सिद्ध होने एवं राजस्व रिकार्ड वादी/रेस्पो0 के नाम दर्ज होने पर ही विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित कर विधि के अनुरूप ही अपीलांट/प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील लगभग 36 वर्ष पश्चात पेश की गई है जिसके बिलम्ब के लिए अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई विधिक कारण अंकित नही किया है केवल मात्र अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी समय पर नही होने का तथ्य अंकित किया है जबकि अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी निर्णय व डिक्री के समय ही हो चुकी थी क्योंकि उनके द्वारा वकालतन दावे का जबाब प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य मनगढन्त है। अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर एवं सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ख0न0 1108/2 रकबा 5 बीघा का आवंटन रेस्पो0 1 ता 4 के पिता हरकचंद पुत्र गुलाबचंद को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27.7.74 को किया गया था। जिसका नामा0 संख्या 1362 दिनांक 26.4.86 को गैर खातेदारी से खातेदारी मे स्वीकार हुआ है। विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खतौनी सम्वत 2041 से 2044 मे रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के पिता हरकचंद के नाम दर्ज है। इस प्रकार रेस्पो0 विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील लगभग 36 वर्ष पश्चात पेश की गई है। जिसके बिलम्ब के संबंध मे किसी प्रकार का कोई विधिक कारण एवं ठोस साक्ष्य सबूत पेश नही किया है जिससे की बिलम्ब के कारण को डिले कण्डोन किया जा सके। इस प्रकार अपीलांट की अपील मियाद अधिनियम से बाधित होने एवं सारहीन होने खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 134/87 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.2.88 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपीलांत अधिकारी
सवाई माधोपुर